1-7-1975 को प्रायोजित जनसंख्या के आधार पर प्रति मास प्रति व्यक्ति 300 ग्राम की उपलब्धता बैठती थी।

(ख) और (ग). केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 27 अक्तूबर, 1977 को लिए गए निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश का चीनी का मासिक कोटा दिसम्बर, 1977 में बढ़ा कर 20,825 मीटरी टन कर दिया गया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच बराबरी का व्यवहार करना सम्भव होगा।

1976-77 में राजस्थान के लिए चावल गेंहूं तथा चीनी

1135 **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के लिए चावल, गेहू और चीनी का कितना कोटा निर्धारित किया गया था, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए राजस्थान सरकार को लगभग 183.5 हजार मीटरी टन गेहूं और 102.7 हजार मीटरी टन चीनी आवंटित की थी। चावल का आवंटन नहीं किया गया था लेकिन राजस्थान सरकार के अनुरोध पर 100 मीटरी टन चावल खासकर उस त्यौहार के संबंध में आवंटित किया गया था।

(ख) इन आवंटनों के प्रति खाद्यान्नों (चावल, गेहू और मोटे अनाज) का कुल उठाव लगभग 516 हजार मीटरी टन हुआ था।

कवि सूरदास पंचशती जयन्ती

1136 **श्री नवाब सिंह चौहान** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार सूरदास की 500 वीं जयन्ती सरकारी स्तर पर मना रही है,

(ख) क्या सूर पंचशती राष्ट्रीय समारोह समिति, मथुरा ने भी इस समारोह को मनाने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यक्रम बनाने का विचार है और सूर पंचशती राष्ट्रीय समारोह समिति, मथुरा को क्या-क्या अनुदान और योगदान देने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति रेणुका देवी बरकटकी): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) महाकवि सूरदास की 500वीं जयन्ती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने हेतु कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने तथा उन्हें समन्वित करने के लिए एक सूर-पंचशती समन्वय समिति गठित की गई है। सूर-पंचशती राष्ट्रीय समारोह समिति, मथुरा तथा देश की अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव समन्वय समिति के विचाराधीन हैं।